भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2129
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

छात्रवृत्ति तथा अनुसंधान और विकास हेतु निधियां

†2129. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसंधान एवं विकास के लिए धनराशि बढ़ाने की कोई विशेष योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास पिछले दस वर्षों में पीएचडी करने के लिए अल्पसंख्यकों को दी गई छात्रवृत्ति के संबंध में कोई डेटा है, यदि हां, तो लिंग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की घटती संख्या के बारे में कोई डेटा है, यदि हां, तो अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप बंद किए जाने के बाद से धर्म-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क): गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुसंधान को एक मुख्य कारक के रूप में मान्यता देते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्र केंद्र, व्यापक उद्योग-अकादमिक संबंध और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषयक अनुसंधान की स्थापना कर अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। सरकार ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय को बढ़ाने और शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए भी कई प्रयास किए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'अनुसंधान और विकास सांख्यिकी पर एक नज़र 2022-23' के अनुसार देश में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है औरवर्ष 2010-

11 में 60,196.75 करोड़ रुपये से दोगुना अधिक होकर वर्ष 2020-21 में 127,380.96 करोड़ रुपये हो गया है।

इसके अलावा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फांउडेशन की स्थापना के लिए " अनुसंधान नेशनल रिसर्च फांउडेशन अधिनियम, 2023" को अधिसूचित किया गया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फांउडेशन, एक शीर्ष निकाय है, जिसकी परिकल्पना गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान, नवोन्मष और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए की गई है। इसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय इंटरफेस को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पांच वर्ष की कुल अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृति (एमएएनएफ) के तहत पिछले 10 वर्षों (2014-15 से 2023-24 तक) में विभिन्न लाभार्थियों को कुल 887 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं, जिनमें 11,114 पुरुष और 13,128 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

*****